

बालाघाट एक्सप्रेस

खास खबर

आईपीएस महेश दीक्षित बने भारत के नए आईबी प्रमुख

नई दिल्ली। भारत को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी महेश दीक्षित को इंटील्लिजेंस ब्यूरो (आईबी) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। आइए प्रोफाइल के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी दीक्षित, निवृत्तमान आरबी निरेशकर तनक कपड़ा देका का स्थान लेंगे। उन्हें सुप्रीम्या नेटवर्क के मामलों में एक विशेषज्ञ और आंतरिकवाद के खिलाफ कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। देश में बदौती अदरबी सुखा को चुनौतियों को काफ़ी अग्रगण्य माना जा रहा है। सुखा से जुड़े पत्रकारिता का कठनाई है कि उनका तबुई और लीडरशिप से इंशुलिके भक्तवृ होनी, साथ ही देशवासि सिकंदरों से जुड़े मामलों में बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।

आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया

बेलफास्ट। मीडिया टी-20 वर्ल्ड चैंपियन भारत को दुनिया में 12वें नंबर की टीम आयरलैंड ने हरा दिया है। बेकनाराम में शुक्रवार को हुए दो मैचों की सीरीज के पहले मुकामले में भारत पर 24 रन से जीत हासिल की। पहले टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस फॉर्मेट में अपना पहला मैच खेले रही थी। यह आयरलैंड के खिलाफ भारत की अब तक की पहली हार भी है। आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। लोकेश ठवर ने 50 रन की पारी खेली। जबकि भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन ही बना सकी। आयरन अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी 20 ओवर पर 50 रन बनाई। न्यूका बल्लेबाज सुब्रह्मण्यम को इस मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला।

अब भीम एप से खुलेगा एनपीएस खाता

नई दिल्ली। देश में पेंशन व्यवस्था को ज्यादा डिजिटल, सरल और आम लोगों को पहुंच में लाने के लिए सरकार और संबन्धित संस्थाएं नए कदम उठा रही हैं। अने वाले समय में लोग भीम एप के जरिए पेंशनल प्रोब्लम रिजल्ट (एनपीएस) में आसानी से खाता खोल सकते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों भविष्य निधि (ईवीकर) को राशि को एनपीएस में स्थानांतरित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इन बदलावों से नौकरशाही कर्मचारियों के अलावा युवा वर्कर्स, छोटे कारोबार और अमीगनोडन के कामगारों को भी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे हैं।

कुछ नया कथन

आघार और पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं

देश को नागरिक न ही सही के वादों होने का सबूत तो तुम्हारे पास है न।



राम मंदिर चढ़ावा- चंपत के ड्राइवर टिबू समेत सभी आरोपियों को भेजा गया जेल

चंपतराय ने दिया इस्तीफा, अनिल मिश्रा की छुट्टी

राम मंदिर चढ़ावा को री सुलना इन आठ लोगों ने स्वी दान चुराने की सजिश



बाथरूम में छिपाते थे कोरे के गोपियों की गाड़ियां

लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा को मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय और टूटरी डायरेक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की इन्जिनियरी थी। राम के बाद टूटरी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सौरभ योगी अयोध्या दौर पर गए थे। उस वक चंपत को उनके दौर से दूर रखा गया था, तभी से यह सुरगुप्तवृद्ध थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, राम के टूटरी का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चलाते मामलों में गुजराट द्वारा टूटरी के सदस्य कुमर मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में परचारी और निगुधर का संकेत दे चुके हैं। सरकार का कहना है कि यदि जांच में किसी भी सर पर अनिर्णयता जा निम्मेदारी तय होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। क्या एफआईआर की अंतिम रिपोर्ट में और चढ़े दुष्कारों को प्रमाणित करने का सबूत आया है? इससे पहले इसी मामले में श्रीराम

पहले विधि विद परिय, फिर टूटरी से जुड़े वंश पराय

चंपतराय विधि विदू परिय के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूटरी के महासचिव पर से इस्तीफा दिया है। राम मंदिर आंदोलन के प्रभुआरती दौर से लेकर निर्माण और उसके संभालन तक उनकी भूमिका मानी जाती रही है। टूटरी के प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया है कि मंदिर संभालने से जुड़े महत्वपूर्ण निगम और नुस्खाने उनके मंत्र तक पहुंचती थीं। वहीं, उनके करीबी और इस्लाम गार्डनर यादव उन्हें टिबू यादव प्रजुल्लों को दान व्यवस्था के साथ-साथ चढ़ावे और दान से जुड़े व्यवस्थाओं को संभालते थे।

लंबे समय से संघ से जुड़े अनिल मिश्रा

श्री अनिल मिश्रा अयोध्या के सीनियर डॉक्टर हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। यह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूटरी के संस्थापक डॉक्टरों में शामिल रहे। टूटरी के मंदिर उदघाटन में अपने बाले चढ़ावे की कैम की निगनी, उसके मुखिया भंडारण और दान करने की व्यवस्था को निगरानी की निम्मेदारी ली गई थी। सूत्रों के अनुसार, मंदिर परिसर की सफाईकार और कुछ अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी उनके कार्यभार में शामिल थी।

एनसीईआरटी ने 9वीं की किताब से संविधान प्रस्तावना हटाई, आपतकाल पर अलग सेक्शन जोड़ा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने अपनी नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हटाया है। जानकारी के अनुसार, इस नए संस्करण में समाजशास्त्र और पंचपरिचय जैसे शब्दों की भी विशेष उल्लेख नहीं है, जबकि आपतकाल (इमरजेंसी) पर एक विस्तृत और अलग खंड जोड़ा गया है। पुस्तक के अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस शैक्षिक वाले अध्यक्ष में, संचिका के निर्माण, लोकार्पणिक संस्थाओं और मूलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, लेकिन संघ, समाजशास्त्र, पंचपरिचय, लोकार्पणिक और गणराज्य जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ या उनकी व्याख्या नहीं हुई है। आपतकाल को लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में दिखाया गया है। किताब में लोकतंत्र का उल्लेख नारायण द्वारा छात्रों और लोगों को संविधान कर विहार और गुजरात में बड़े जन आंदोलनों को खड़ा करने की भूमिका पर भी विचारित से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 1977 में आपतकाल का समाप्त होने के बाद हुए आम चुनावों में जनता ने अपने मतानिर्णय के माध्यम से सत्ताहस्त संस्कार को दूर किया, इस भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण माना गया है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधामंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही संविधान पर 1976 में पंचपरिचय, समाजवादी और अखंडता खंड जोड़े थे, हालांकि वे खंड अभी भी भारतीय संविधान का हिस्सा हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में 1970 के दशक को शुरूआत में इंदिरा सरकार के खिलाफ बहती जन नारायणी, बेरोगामी, महंगाई और कुर्बानियों के आरोपों के कारण हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र है, जबकि बाद तु 1975 में आंतरिक सुरक्षा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। किताब के अनुसार, आपतकाल के दौरान अतिरिक्त मौलिक अधिकार निर्यात कर दिए गए, इस पर संसदीय लाइफ गार्ड और कई राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़े दबाव और लोगों की स्वतंत्रता के सीमित होने के दौर के रूप में वर्णित किया गया है।

रतलाम में हाई-टेंशन लाइन से टकराया ताजिया, 3 की मौत

रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुहम्मद जुनुस के दौरान ताजिया के हाई-टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादासा हुआ। घटना में तीन लोगों की दर्दनक मौत हो गई, जबकि अन्य घन सत अन्य घायल हुए हैं। यह दुर्घटना घटने के 24 घण्टों में तय हुई, जब करकोई की संख्या में लोग ताजिया के साथ जुलूस निकाल रहे थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे। तभी ताजिया का खंडा उलटने से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे कई लोगों को बिजली का जहरदार झटका लगा और वे हलत गए। अचानक हुई सत से जुलूस में अफरातफरी मचा गई। मुताकों की पहचान राहुल खान, सडू हद्दीन और अखतार खान के रूप में हुई है। घायलों को तुरंत तहसील मेडिकल कॉलेज और आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहाँ पौच लोगों को हलत गंभीर है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौक पर पहुंचे। एम्बुसी रोकेंस पाण्डों ने बताया, जिसमें कई लोगों को बिजली का जहरदार झटका लगा और वे हलत गए। अचानक हुई सत से जुलूस में अफरातफरी मचा गई। मुताकों की पहचान राहुल खान, सडू हद्दीन और अखतार खान के रूप में हुई है। घायलों को तुरंत तहसील मेडिकल कॉलेज और आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहाँ पौच लोगों को हलत गंभीर है।

सत्य, न्याय और साहस की राह दिखाती है कर्बला की कुर्बानी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को ब्रह्मअंधित होने के लिए कहा कि उनका बलिदान आजी की करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और साहस के मार्ग पर उठे रहने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने सांख्य मीडिया चैनल 'पुस्तक' पर जारी अपने संदेश में इमाम हुसैन की कुर्बानी को साहस, दूर संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक बताया।

हजरत फातिमा के छोटे पुत्र थे। इस्लाम के इतिहास में उनका त्याग अत्यंत समन्वयपूर्ण माना जाता है। वर्ष 680 ईस्वी (61 हजिरी) में इराक के कर्बला में उन्होंने सत्य, न्याय और साहसिता की राह के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इमाम हुसैन ने तत्कालीन मुसलमन युवाओं को सता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कर्बला के मैदान में उन्होंने पवित्र परिवार और साहित्यों में सत्य कतिन परिस्थितियों में संघर्ष किया और शहादत प्राप्त की, लेकिन अन्याय के सामने झुकने नहीं।

अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक

कर्बला की घटना को आज भी अन्याय और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के समेत बड़े प्रतीकों में माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा का संदेश देती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा, युवाओं, किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संस्कार जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा कि नात प्रतियक्ष के रूप में बतें दो साल पूरे। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में देश को बताने की चुनौती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा, युवाओं, किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संस्कार जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा कि नात प्रतियक्ष के रूप में बतें दो साल पूरे। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में देश को बताने की चुनौती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा का प्रयास किया है।

अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक

कर्बला की घटना को आज भी अन्याय और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के समेत बड़े प्रतीकों में माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा का संदेश देती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा, युवाओं, किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संस्कार जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा कि नात प्रतियक्ष के रूप में बतें दो साल पूरे। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में देश को बताने की चुनौती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा का प्रयास किया है।

ऑनलाइन धोखाधड़ी पर आरबीआई का नया नियम : ग्राहकों को 25,000 तक मुआवजा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बड़ों मामलों के बीच उधेकाओं को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब युपीआई, नेचू बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वेबिचू या क्रॉडिचू काउंट जैसे डिजिटल माध्यमों से हुए धोखाधड़ी में ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है, भले ही धोखाधड़ी में आंशिक रूप से उनकी लापरवाही भी शामिल हो। यह कदम तब उठाया गया है जब ऑनलाइन फंड के पीछे की सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर जलिल प्रक्रिया होती है। 24 जून, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, नियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा और इस प्रावधान को उसके बाद लागू किया जाए सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर लागू होगा। यह प्रावधान सचिव फाइनेंस बैंकों, पेमेंट बैंकों, क्षेत्रीय प्राथमिक बैंकों और

स्थायी क्षेत्र बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा। यह नए दिनांकित डिजिटल भूगोलन के हर पहलू को कवर करे है, चाहे वे कार्ड आधार या टेप के माध्यम से किए गए हों, या ऑनलाइन कार्ड विचारण दर्ज करके।

ग्राहकों की लापरवाही-यह अधिसूचना का सबसे नया और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धोखाधड़ी में ग्राहकों की लापरवाही भी शामिल थी, जैसे कि अनौपचारिक साक्षात्कार, फिंगरिंग लिंक कर लिंक करण, या सदिष्ट एप डाउनलोड करण, तब भी उन्हें मुआवजा मिल सकता है। यह प्रावधान ने दुरुत कार्रवाई की हो।

नए नियमों के तहत, मुआवजे की अधिकतम राशि 25,000 रुपये या धोखाधड़ी की राशि का 85 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो। यह मुआवजा किसी भी एक व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति

के साथ 50,000 रुपये की धोखाधड़ी होती है और वह रिक्वायर्ड दर्ज करता है, तब उस अधिकतम 25,000 रुपये का ही मुआवजा दिया जाएगा।

मुआवजे का भूगोलन रिजर्व बैंक, ग्राहक का बैंक और लाभार्थी बैंक मिलकर करण करते हैं। 29,412 रुपये से कम के नुकसान वाले मामलों में, आरबीआई 65 प्रतिशत, ग्राहक का बैंक 10 प्रतिशत और लाभार्थी बैंक 10 प्रतिशत का योगदान करने वाले हैं। वहीं, 29,412 रुपये से 50,000 रुपये तक के नुकसान के मामलों में, जहाँ मुआवजा 25,000 रुपये है, आरबीआई 19,118 रुपये, ग्राहक का बैंक 2,941 रुपये और लाभार्थी बैंक 2,941 रुपये का योगदान करणगे। यह पहला डिजिटल लेनदेन के ग्राहकों के विधायकों को मजबूत करने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दो साल पूरे

-वीडियो जारी कर विनाई उपलब्धियां, बोले- हर भारतीय की आवाज संवाद तक पहुंचाती रहूंगा

नई दिल्ली। लोकसभा में नात प्रतियक्ष के रूप में दो वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस संसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर अपने कार्यकाल के प्रमुख मुद्दों और प्रतिनिधित्वों को देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों में उनका उद्देश्य देश के हर नागरिक को आवाज को संवाद तक पहुंचाना और उनके भी वह जनता से जुड़े मुद्दों को संवाद से संवाद तक उठाये रहने। करीब 3 मिनट 29 सेकंड की इस वीडियो किण्वण को सांख्य मीडिया चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा, युवाओं, किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संस्कार जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा कि नात प्रतियक्ष के रूप में बतें दो साल पूरे। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में देश को बताने की चुनौती है। उनकी कुर्बानी सचियों चैनल 'पुस्तक' पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान की रक्षा का प्रयास किया है।



लगातार महंगे हो रहे खाद, बीज, कीटनाशक ने किसानों की चिंता बढ़ाई खेती अब लाभ का नहीं कर्ज और आर्थिक संकट का सौदा



पद्मेश न्यूज। लांजी। देग में खेती-किसानों लगातार महंगे हो रही है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल-पेट्रोल, सिंचाई और मजदूरी की बढ़ती लागत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर कृषि उपज के अपेक्षित दाम नहीं मिलने से किसानों को आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि खेती अब लाभ का नहीं, बल्कि कर्ज और आर्थिक संकट का सौदा बनती जा रही है। कृषि विशेषज्ञों और श्रेयशेखर किसानों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में खेती के लिए आवश्यक लागतमा समी कृषि आदानों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद और बीज के दाम बढ़ने के साथ-साथ डीजल, सिंचाई तथा मजदूरी पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसके विपरीत फसलों के समर्थन मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से किसानों को आर्थिक दिक्कत का सामना हो रही है। उत्पादन लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसएम) के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। खेती में लगने वाली लागत, समय और मेहनत को तुलना में मिलने वाला मूल्य पर्याप्त नहीं है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकारी खेती को लाभकारी बनाने और उत्पादन बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन बढ़ती लागत के अनुपात में राहत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मत इसी प्रकार बढ़ती रही और उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला, तो कृषि क्षेत्र में संकट और गहरा सकता है। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए,

हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों को वास्तविक लागत का मूल्यांकन कर खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

राजू मेंटे ने की टोस नीति की मांग

पूर्व जनपद सदस्य राजू मेंटे ने कहा कि खेती देश की अर्थव्यवस्था को रोह है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किसान सबसे अधिक आर्थिक दबाव झेल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को उनका उपज का उचित मूल्य नहीं मिला और कृषि लागत पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो खेती से किसानों का मोहभंग हो सकता है।



सरकार को किसानों के हित में टोस, व्यावहारिक और दीर्घकालिक नीति बनकर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि खेती को पुनः लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खेती लागत और घटती आय के इस संकट से किसानों को उबारने के लिए सरकार, कृषि विभाग और नीति निर्माताओं को समन्वय प्रदान करनी चाहिए। तथा खेती को लाभकारी बनकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा।

खण्डाफरी वन समिति चुनाव संपन्न, नरेंद्र कुमार टिकले बने अध्यक्ष



पद्मेश न्यूज। लांजी। वन विभाग पश्चिम लांजी अंतर्गत खण्डाफरी वन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण एवं उदासीनपण मानील में संपन्न हुआ। चुनाव में तीन प्रत्याशियों ने अपना भाग आजमाया, जिसमें नरेंद्र कुमार टिकले ने 259 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। प्रात जानकारी के अनुसार समिति में कुल 925 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 566 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान के दौरान 6 मत अमान्य (रिजेक्ट) पाए गए। मतगणना के बाद घोषित परिणामों में नरेंद्र कुमार टिकले को 259 मत, चंद्रकुमार सरटे को 193 मत तथा देवेंद्र कुमार किरमे को 108 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार नरेंद्र कुमार टिकले विजयी घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया का सफल संचालन डिप्टी रेंजर रविन्द्र सोनवानी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नरेंद्र कुमार टिकले की जीत पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने उन्हें

बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। बधाई देने वालों में अजय अचरवे (उपच्यक्ष जनपद पंचायत लांजी), दिनेश लाडे (सभापति जनपद पंचायत लांजी), राजू सोयाम (सरसंख खण्डाफरी), प्रमोदपाल किरमे (सरसंख टेकर), गोवर्धन टिकले (पूर्व सरसंख), किशोरलाल खरे, महेश टिकले, जगत टिकले, इंद्रधरदास देहिकर, तिलकराज आरवे, भिरालाल टिकले, कन्हैयालाल टिकले, रूपचंद्र बाहे, तपरीलाल टिकले, गणेशलाल खरे, भवकिशोर टिकले, धर्मो नेताम, भरत टिकले, पुरुषोत्तम चालक, बलराम टिकले, मोहन वरकडे, राजेश टिकले, परीधर खरे, राजेश चोपड़ा, मनोहर खरे, गोपालदास खरे, गणेश टिकले, तेजलाल नागधर, फुलदास पांचे एवं विष्णु टिकले सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल रहे। विजय की घोषणा के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया तथा नव निर्वाचित अध्यक्ष को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई।

राष्ट्रीय पल्ल पोिलियो अभियान अंतर्गत 28 जून को पीलाई जाएगी पल्ल पोिलियो दो बूँद जींदगी की

पद्मेश न्यूज। लांजी। 28 जून दिव रविवार को म.प्र. शासन के निर्देशानुसार, डॉ. चंरा उलपल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट से प्राप्त निर्देशन में विकास खण्ड लांजी क्षेत्र में पल्ल पोिलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोिलियो ड्रॉप की दो बूँद जींदगी की पीलाई जाएगी। डॉ. अश्वय कुमार उपराडे, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल लांजी द्वारा यह बताया गया कि अभियान के प्रथम दिव 28 जून को विकासखण्ड लांजी के अंतर्गत 0 से 05 वर्ष तक के कुल 15310 बच्चों को पोिलियो ड्रॉप मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोिलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 192 बूय बनाए गए हैं, जिनमें 384 बुधबचकों द्वारा तथा 25 सुपरवाइजरों के सुपरविजन में बच्चों के अनमोल जीवन के लिये दो बुँद पोिलियो की दवा पीलाई जाएगी। सावा ही 61 से. टीम घर-घर भ्रमण कर बच्चों को पोिलियो दवा पीलाएगी व 131 को टीम प्रथम दिवस बुध में व आगामी दो दिनों में घुंटे हुए बच्चों को घर-घर जाकर पोिलियो दवा पीलाकर शतातिशत लक्ष्य प्राप्ति का कार्य करेगी। विकासखण्ड में विविध आवागमन के साधनों से प्रवेश करने वाले लोगों के बच्चों को भी पोिलियो दवा के माध्यम से प्रतिरक्षा करने के लिये 05 जूनोड टिम बनाई गई है जो बस स्थानों, बैंक पोस्ट व अन्य स्थानों में दवा पीलाने के कार्य करेगी। उनका तक पोिलियो अभियान को सफल बनाने के लिये बैठकों का आयोजन किया गया एवं ग्रामों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लेखन कार्य किया गया। डॉ. अश्वय कुमार उपराडे खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्षेत्र को जनाता को अधिक से अधिक बच्चों को दवा पीलाकर पोिलियो मुक्त करने के राष्ट्रीय अभियान में योगदान देने की अपील की है।



बदहाल हुआ बकरामुंडी वनोपज नाका बारिश में कर्मचारी कैसे करेंगे ड्यूटी



पद्मेश न्यूज। लांजी। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत परिक्षेत्र पूर्व लांजी के अधीन आने वाले बकरामुंडी वनोपज नाका के भवन की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लंबे समय से मरम्मत की उपाक्ष के कारण नाका भवन की छत एक ओर से गिर चुकी है तो दूसरी ओर भी पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जिससे बारिश के मौसम में यहां सैनत कर्मचारियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। कर्मचारी बारिश में कैसे ड्यूटी करेंगे और कैसे रहेंगे, यह सवाल इन दिनों यहां सभी को परेशान कर रहा है। नाका भवन की छत बरस और कलेव से बनी हुई है, जो अब पूरी तरह सड़ चुकी है एवं पानी गिरने के कारण दीवारें भी गिरने लगी हैं। भवन की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कर्मचारी तिरपाल या किसी अन्य अस्थायी व्यवस्था से भी छत को टुकने में असमर्थ हैं। छत की कमजोरी संरचना के कारण तिरपाल चढ़ाने का प्रयास भी खतरनाक साबित हो सकता है।



लंबे समय से लापरवाही वन विभाग के सूची के मुताबिक, इस नाका को मरम्मत का प्रस्ताव कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया और बजट की कमी के चलते काम रुका पड़ा है। स्थानीय स्तर पर

छोटी-मोटी मरम्मत कराई गई, लेकिन गौसमी क्षति के आगे ये ठिक नहीं पाई।
इन्का कहना है
वन परिक्षेत्र अधिकारी सपन तायकर से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि निश्चित ही यह समस्या पूर्ण रूप से क्षीरमत्त हो गया है, एवं बारिश में वहां कर्मचारी नहीं रह पाएंगे। हम कर्मचारियों की समस्या से अवागत हैं। विभाग को भवन निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही ठोस कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के मौसम के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी जिससे कि कर्मचारियों की ड्यूटी प्रभावित न हो।

मप्र के 15 जिलों में मानसून सक्रिय

भोपाल। मप्र में अब तक 15 जिलों-अलोरपुर, बुंदेल, हरदा, धार, बैतूल, खंडवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पाण्डुर, खरगोन, सिधौरी, बालाघाट, मंडला, बड़वानी, छिंदौरी में मानसून के आने की घोषणा हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं कई जगह आकाशीय बिजली भी गिरी है। इस कारण प्रदेश में 5 लोगों को मौत हो गई।
बालाघाट के बेहद तहसील के किरवा ग्राम पंचायत में बिजली गिरने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों को मौत हो गई, जबकि 6 लोग घुलस गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मी मेरानी, श्यामिनि शर्मा (35) और सखीश बलके के रूप में हुई है। वहीं, देवघाट के खडवा गांव में सूरज की पूजा के दौरान आंधी-बारिश से गैलरी गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं को मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मीदेवी और भाग्यताईबाई के रूप में हुई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग

तक पहुंच जाएगा। स्थानिय-चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में मानसून सबसे आदिमर में बरसक देगा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश हुई। संभवतः ज्यादा करीब 2 इंच बारिश शाबापुर और नवादासगंज में दर्ज की गई, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली।
शुजालपुर में 2 घंटे झमाझम बारिश, जलभराव
शाबापुर जिले के शुजापुर में शुक्रवार दोपहर करीब दो घंटे तक मुसलधार बारिश हुई। कई सड़कों और निचले इलाके जलमग्न हो गए। गणेश मंदिर माना की भीतर नंबर-2 में पानी भरने से मकड़ समथ के लिए आवागमन प्रभावित रहा। इस मामला में अज तक शुजापुर में 130 मिमी बारिश हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी है।
अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों को बुवाई भी तेज कर दी है। शाबापुर शहर के हारामपुर स्थित मंगलमूर्ति हनुमान मंदिर परिसर में तेज हवा के चलते वर्षा

पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। घटना गुरुवार को हुई थी, जिसका मोसीटीवी फुटेज शुक्रवार शाम सामने आया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मंदिर परिसर में कोई भी नहीं था, जिससे बड़ा हासा टल गया।
मंदसौर में भी बारिश से बदला मौसम
मंदसौर शहर स्थित मल्लारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, दलीवा और बही पार्कनाथ समेत कई इलाकों में शुक्रवार दोपहर अच्छी बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और किसानों को भी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाली दिनों में फिले में बारिश का संभावित बानी रहने की संभावना है। देवास के खडवा गांव में सूरज पूजा कार्यक्रम के बाद भोजन का आयोजन चल रहा था। पर के सामने टेक लगाया गया था और ऊपर नेट भी बंधी हुई थी। इसी दौरान करीब 150 से 200 लोग पंगत में बैठकर भोजन कर रहे थे। इसी बीच अचानक तेज हवा, आंधी और बारिश शुरू हो

गई। मौसम विभागने ही मकान की छत को गैलरी भरपराकर नीचे गिर गई। गैलरी सीधे सन पंगत पर गिरी, जहां महिलाएं बैठकर भोजन कर रही थीं। हादसे में कई लोग मलबे की चोट में आ गए। घटना के बाद मीके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गैलरी गिरने को आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए लगा जैसे बादल फट गया हो।
आगर मालवा में सड़कें पानी से लबाब
आगर मालवा में शुक्रवार शाम मौसम से अचानक करफट ली और करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई। शनिवार 4:15 बजे शुरू हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबाब हो गईं। छावनी, बड़ोद चौराहा और उज्जैन रोड समेत कई इलाकों में जलभराव होने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

लांजी में "पद्मेश"

इंटरनेट (ब्राडबैंड)

कनेक्शन के लिये संपर्क करें

Mo. 8319969927

लोकतंत्र सेनानियों के लिए सीएम यादव की बड़ी घोषणा

स्पेशल ट्रेन से तीर्थयात्रा, सर्किट हाउस में दो दिन ठहरने की सुविधा

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए तीर्थयात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने, प्रदेश के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में दो दिन निःशुल्क ठहरने, मुद्रा इलाज और एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध करने का ऐलान किया। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों को मूर्ति में उनके गंध-कर्मों में शिलालेख स्थापित करने तथा पार्क, मार्ग और खेल मैदानों का नाम उनके नाम पर रखने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताम्रपत्र से बंधित लोकतंत्र सेनानियों को भी ताम्रपत्र सम्मानित किया जाएगा। बला में ताम्रपत्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान-पत्र होता है। यह तब की वरिष्ठ या निम्न-प्रमाण-पत्र के रूप में प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र सेनानियों के



लोकतंत्र सेनानियों के लिए ताम्रपत्र यह प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति ने 1975-77 के आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लोकतंत्र सेनानी के रूप में मान्यता दी गई है।

सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दोस दिन प्रवृत्तित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोकतंत्र सेनानियों पर उच्च कर्मा चक्र उनका सम्मान किया। इस अवसर पर 96 वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार, 95 वर्षीय

शॉल लाल संपुर्ण तथा पूर्व मंत्री उमाकरंकर गुला को विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

आपकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन की दूसरी लड़ाई के समान था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के कठिन दौर में लोगों को विना अंगुली, बिना दलील और बिना सुनवाई जैसी में डल दिया जाता था। ऐसे समय में लोकतंत्र को रक्षा के लिए जिन्हें लोगोंने संघर्ष किया, उन्हें ही सबसे बड़ा आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि परिवार से निकला व्यक्ति आज देश का

प्रधानमंत्री बन सकता है, यह लोकतंत्र की ताकत है।

कांग्रेस ने संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और एक परिवार की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से विकास कर रहा है, जबकि भारत के साथ आजाद हुआ पाकिस्तान लोकतांत्रिक अस्थिरता से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ ने हर कठिन समय में राष्ट्रहित में अपनी भूमिका निभाई है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादले को लेकर लगाई कैविएट

- 28 से 30 जून के बीच जारी होंगे आदेश, संयुक्त संवत्सक प्र कार्यों के तबादले भी हुए

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीच्छक तबादलों को लेकर शिक्षकों के विरोध को दबाने के लिए अब संभावित कानूनी चुनौती से निपटने को तैयारी भी शुरू कर दी है। विभाग ने स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। इसके साथ ही संयुक्त संवत्सक, प्रशासन और अन्य अधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सहायक संचालकों की परदेशना के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब 24 तक ऑनलाइन प्राप्त स्वीच्छक तबादला आवेदनों के आधार पर भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।

लोक शिक्षण संस्थानालय ने विभागीय स्थानांतरण नीति-2026 के तहत संभावित कानूनी विवादों को देखते हुए कैविएट दायर कर दी है। विभाग के अनुसार प्रशासनिक एवं स्वीच्छक आधार पर स्थानांतरण आदेश 28 से 30 जून 2026 के बीच जारी किए जाएंगे। विभाग को आशा है कि तबादलों के बाद कई कर्मचारियों हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय विभाग का पक्ष सुनने का अधिकार आदेश जारी न करे, इसके लिए पहले से ही कैविएट दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवत्सकालय ने 25 जून को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर कर्मचारियों और आमजन को भी अवगत करवाया है।

राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत नल जल योजना संचालन संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 किया जारी...

अब गांवों को देना होगा पानी का टैक्स

भोपाल। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के गांवों में नल जल योजना को पहुंचाव, लैंकिंग अथवा योजना को लागू कर पंचायत रखने के लिए पंचायतें लोगों से इसका ठेका भी वसूलेंगी। इसके लिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत नल जल योजना संचालन संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 जारी कर दिए हैं। नल जल योजना के प्रबंधन के लिए पंचायतों को योजना के रखरखाव, नए कनेक्शन, बिजली लैंकिंग से लेकर इस सब के लिए देना शुरू करने तक के अधिकार दे दिए हैं।

राज्य सरकार ने जल कर वसूल का निर्णय भी तय कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल कर के रूप में हर माह 100 रुपए प्रतिमाह रशि ली जाएगी। नल जल योजना के पानी का नलन उपयोग करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

पंचायतों को लेकर नए नियम में कई प्रवधान

नारीय निकायों के बाद अब पंचायतों में भी नल जल योजना के लिए नए प्रभार निर्धारण किये और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण एकाज प्रदान योजना के लिए बिजली वितरण का भुगतान निकायों के हर माह करना होगा। इसका प्रबंधन संबंधित पंचायत को ही करना होगा। पंचायतों की यह

भी जिम्मेदारी होगी कि वह पानी को फिल्टर छावों को ठेके और यदि कोई पात्र लाइन अधिग्रहण होती है, जो वह उसकी मरम्मत करेगा। नए पानी कनेक्शन कराने में नए नियमों के तहत अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी हर माह पानी के पानी के लिए निर्धारित रशि का भुगतान करना होगा। यह रशि 100 रुपए से 120 रुपए प्रतिमाह हो सकती है। आदिवासी विकासखंडों में फिल्टर उपभोक्ताओं से 60 रुपए प्रतिमाह की रशि ली जाएगी। इसके पर के लिए नया कनेक्शन लेने के लिए 1 हजार रुपए से लेकर कई हजार रुपए तक की रशि का भुगतान करना होगा। इसमें एससी-एसटी परिवारों को नए नल कनेक्शन के लिए 1 हजार रुपए, जबकि अन्य परिवारों को इसके लिए 2500 रुपए की रशि देनी होगी। यदि पंचायतों में किसी व्यक्तिव्यक्ति गतिविधि के लिए नल कनेक्शन दिया जाता है, तो इसके लिए 8000 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।

अवेदन के 30 दिन में मिलेगा कनेक्शन
पंचायत में नया पानी कनेक्शन के लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। पंचायतों की जिम्मेदारी होगी

के बेटे देवराज सिंह गुर्जर की शिक्षायात्र पर नौ लोगों के खिलाफ माफीपत्र, अद्वैताना समेत बाहर भूमिका से कोटिप्र प्रकाश दिश्व गुर्जर के बेटे से मारपीट और अद्वैताना की घटना में पुलिस ने देर दान वैरावटी करते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस वरिष्ठ ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी विधायक पुंड और उसके सहयोगियों पर चारों ओर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तार बुकनों की मां तथा यादव का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके बेटों के साथ मारपीट की गई। मामलों में पुलिस ने विधायक

को रिपोर्ट रख सकेगी। इसका भुगतान लिए जाने वाले सब प्रभार को रशि में से किया जाएगा।

पानी के लिए हर माह करना होगा भुगतान

नए नियमों के तहत अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी हर माह पानी के पानी के लिए निर्धारित रशि का भुगतान करना होगा। यह रशि 100 रुपए से 120 रुपए प्रतिमाह हो सकती है। आदिवासी विकासखंडों में फिल्टर उपभोक्ताओं से 60 रुपए प्रतिमाह की रशि ली जाएगी। इसके पर के लिए नया कनेक्शन लेने के लिए 1 हजार रुपए से लेकर कई हजार रुपए तक की रशि का भुगतान करना होगा। इसमें एससी-एसटी परिवारों को नए नल कनेक्शन के लिए 1 हजार रुपए, जबकि अन्य परिवारों को इसके लिए 2500 रुपए की रशि देनी होगी। यदि पंचायतों में किसी व्यक्तिव्यक्ति गतिविधि के लिए नल कनेक्शन दिया जाता है, तो इसके लिए 8000 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।

अवेदन के 30 दिन में मिलेगा कनेक्शन

पंचायत में नया पानी कनेक्शन के लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। पंचायतों की जिम्मेदारी होगी

सविदा कर्मियों के ट्रांसफर अवैध - हाईकोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुधमान प्रभार प्रभारमंत्रि जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय अप्रतिष्ठ निति नहीं पकड़ पा रहा है। राज्य में इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 26.01 लाख है, लेकिन अब तक केवल 15.66 लाख वरिष्ठ नागरिकों के ही आयुधमान कार्ड बन पाए हैं। इसका मतलब है कि करीब 10.35 लाख बुजुर्ग अभी भी योजना के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सरकारी की ओर से मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की निशुल्क उपचार सुविधा का लाना नहीं मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत बताने हैं कि कई मिलने में आवेदन और कार्ड निर्माण में देहांत प्रवधान किया है, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी तक योजनाओं की पहुंच अभी भी अधूरी है। स्वस्थे बड़ी चुनौती पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण है। बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है। विचार्यों का मानना है कि यदि अधिभारण को बंद कर दिया जाए तो सभी पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य समय पर पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

पेपर लीक के बाद अब किताने भी लीक

पेपर लीक के बाद अब किताने भी लीक

एमपी में 10.35 लाख बुजुर्ग अब भी आयुधमान योजना से बाहर

भोपाल। मध्य प्रदेश में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुधमान प्रभार प्रभारमंत्रि जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय अप्रतिष्ठ निति नहीं पकड़ पा रहा है। राज्य में इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 26.01 लाख है, लेकिन अब तक केवल 15.66 लाख वरिष्ठ नागरिकों के ही आयुधमान कार्ड बन पाए हैं। इसका मतलब है कि करीब 10.35 लाख बुजुर्ग अभी भी योजना के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सरकारी की ओर से मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की निशुल्क उपचार सुविधा का लाना नहीं मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत बताने हैं कि कई मिलने में आवेदन और कार्ड निर्माण में देहांत प्रवधान किया है, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी तक योजनाओं की पहुंच अभी भी अधूरी है। स्वस्थे बड़ी चुनौती पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण है। बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है। विचार्यों का मानना है कि यदि अधिभारण को बंद कर दिया जाए तो सभी पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य समय पर पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

आवेदन से इंटर अक्टवल, भोपाल उठे स्थान पर

आवेदन से इंटर अक्टवल, भोपाल उठे स्थान पर

कर्मियों के ट्रांसफर अवैध - हाईकोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुधमान प्रभार प्रभारमंत्रि जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय अप्रतिष्ठ निति नहीं पकड़ पा रहा है। राज्य में इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 26.01 लाख है, लेकिन अब तक केवल 15.66 लाख वरिष्ठ नागरिकों के ही आयुधमान कार्ड बन पाए हैं। इसका मतलब है कि करीब 10.35 लाख बुजुर्ग अभी भी योजना के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सरकारी की ओर से मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की निशुल्क उपचार सुविधा का लाना नहीं मिल पा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत बताने हैं कि कई मिलने में आवेदन और कार्ड निर्माण में देहांत प्रवधान किया है, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी तक योजनाओं की पहुंच अभी भी अधूरी है। स्वस्थे बड़ी चुनौती पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण है। बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है। विचार्यों का मानना है कि यदि अधिभारण को बंद कर दिया जाए तो सभी पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य समय पर पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

आवेदन के 30 दिन में मिलेगा कनेक्शन

पंचायत में नया पानी कनेक्शन के लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। पंचायतों की जिम्मेदारी होगी

मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे से मारपीट कराने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। अंतरा हिल्स तथा इलाकों में स्थित विधायक विश्राम गुर् (एमएलए रेंटर हाउस) के बाहर भूमिका से कोटिप्र प्रकाश दिश्व गुर्जर के बेटे से मारपीट और अद्वैताना की घटना में पुलिस ने देर दान वैरावटी करते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस वरिष्ठ ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी विधायक पुंड और उसके सहयोगियों पर चारों ओर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तार बुकनों की मां तथा यादव का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके बेटों के साथ मारपीट की गई। मामलों में पुलिस ने विधायक

के बेटे देवराज सिंह गुर्जर की शिक्षायात्र पर नौ लोगों के खिलाफ माफीपत्र, अद्वैताना समेत बाहर भूमिका से कोटिप्र प्रकाश दिश्व गुर्जर के बेटे से मारपीट और अद्वैताना की घटना में पुलिस ने देर दान वैरावटी करते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस वरिष्ठ ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी विधायक पुंड और उसके सहयोगियों पर चारों ओर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तार बुकनों की मां तथा यादव का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके बेटों के साथ मारपीट की गई। मामलों में पुलिस ने विधायक

निवासी रोहन यादव अपने ममेरे भाई हनी के साथ कार से एमएलए रेंटर हाउस पहुंचा था। इसी दौरान उसकी कार वहीं खड़ी दूसरी कार से हटके से टकरा गई और दोनों पक्षों के बीच कड़ाहंगु हो गई थी। मारपीट में विधायक पुंड देवराज को चोट आई है। देवराज गुर्जर विमान्त करते हैं, और परिवार के साथ रेंटर हाउस में रहते हैं। उनका कहना है कि बुधवार तल करीब साढ़े 12 बजे वह खाना खाकर एमएलए रेंटर हाउस की बालकनी में रहने लगे थे। उसी दौरान रेंटर हाउस के नीचे कुछ शोरक शोरक गंगाक गंगाक की नजर आया। देवराज ने नीचे जाकर उन्हें परिचय से जाने के लिए कहा।

पेपर लीक के बाद अब किताने भी लीक

- कांग्रेस ने एनसीईआरटी और केंद्र सरकार को घेरा, राष्ट्रपति को पत्र लिख दी जानकारी

भोपाल। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक शिवाजी ने एनसीईआरटी और केंद्र सरकार को घेरा, राष्ट्रपति को पत्र लिख दी जानकारी

संस्कृत से हुई जिसे जारी कर एनसीईआरटी ने देश के अधिभावकाओं को नकली कितानों से सलाहना रहने की नहिदत दी, पत्र को ले कर अधिभावकों में नारबगी नजर आई उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि एक और नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सतती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का दावा करने

का अंतर्गत लाया जा सकता है। शिवाजी ने कहा कि आज देश में अधिभावक निजी स्कूलों की मारमारी फीस, निर्धारित दुकानों से कितानों और ट्रेड दुकानों की मजबूती तथा शिक्षा के बढ़ते हैं। इन मुद्दों को लेकर कानून प्रवधान जनआंदोलन और विचार्य प्रवधान का लक्ष्य है। अब पत्र लौकिक के बाद कितानों के लौक होने की घटनाएं बढ़ सावित कर रहे हैं। कि प्रवधान राज में शिक्षा व्यवस्था पर माफिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनके खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी अधिभारण छत्रों

राज्यपाल मंगू भाई पटेल का बड़ेगा कार्यकाल !

भोपाल। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है। यद्यपि है कि उनका कार्यकाल एक और टर्म बड़ सकता है। उन्हें प्रभारमंत्रि नरेंद्र मोदी का विस्थापना माना जाता है। राज्यपाल के रूप में उनका पूरा कार्यकाल बिना किसी विवाद के रहा है। और उनका दुर्भाग्यवश राज्य सरकार से काफी अच्छी है। इन सब विचार्यों को देखते हुए मंगू पटेल का कार्यकाल बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह खबर तेज हो गई है कि उन्हें एक बार फिर राज्यपाल पर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर राष्ट्रपति किसी नए चहरे को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करेंगे। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति भवन स्तर पर लिया जाएगा।

हालांकि नए राज्यपाल को नियुक्ति होने तक वर्तमान राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे में यदि तत्काल नई नियुक्ति नहीं होती है, तो मंगूभाई पटेल पद पर बने रह सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार जल्द ही कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों और फेरबदल पर फैसला ले सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी इस सूची में शामिल हो सकता है। हालांकि उनका एक बड़ा संस्कार या राष्ट्रपति भवन की ओर का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिलता है। अब निर्णय किस संतक पर टिकी है कि राष्ट्रपति मंगूभाई पटेल को कार्यकाल विस्तार देती हैं या मध्य प्रदेश को कार्यकाल विस्तार मिलता है।

आदिवासी क्षेत्रों पर रक्षा विशेष फोकस

गुजरात से आने वाले वरिष्ठ भाषण नेता मंगूभाई छत्रमण्डल पटेल ने 7 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में देवराज दिश्व गुर्जर था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विशेष ध्यान से आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका

पिछले 15 वर्षों में दूसरा पूरा कार्यकाल

पिछले डेढ़ दशक में मंगूभाई पटेल दूसरे ऐसे राज्यपाल होने, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना पूरा पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले राममोहन यादव को 8 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 7 सितंबर 2016 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद राज्य में राज्यपाल पद पर कई बदलाव हुए। आम प्रकाश कोहली ने अंतरिक प्रभार संभाला, फिर आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनीं। उनके बाद लालजी टंडन ने जुलाई 2019 से जून 2020 तक जिम्मेदारी निभाई। लालजी टंडन के निधन के बाद एक बार फिर उमर प्रशर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अंतरिक प्रभार दिया गया। इसके बाद 7 जुलाई 2021 को मंगूभाई पटेल ने राज्यपाल का पद संभाला।

राठायरमें से पहले जान सकेंगे कितनी मिलेगी लीव इनकैशमेंट राशि

भोपाल। मध्य प्रदेश के लार्डों सरकारी कर्मचारियों के लिए राशि को खबर है। अब सेवा पर अंतिम अवकाश का नकदकरण कर चुका है, तो जाने दिनों को 300 दिन की अधिकतम सीमा से घटता जाएगा। (अवकाश नकदीकरण) को गणना को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए एमपी विभाग में एक समान प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं।

गणना को लेकर खतरा होगा भ्रम

अब तक विभिन्न विभागों में लीव इनकैशमेंट की गणना अलग-अलग तरीके से की जाती थी। इससे भ्रम और भ्रमनाश को लेकर कर्मचारियों और विभागों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती थी। विन विभाग का मानना है कि नए दिशानिर्देश लागू होने से पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू होगी और भ्रमनाश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष मुक्त बनेगी। गौतमलव ने कि सरकारी सेवा में दीर्घ कर्मचारियों के खाले में अंतिम अवकाश जान होता रहा है। अधिकांश कर्मचारी अपनी सभी सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण बड़ी संख्या में इंतजाम बंद जाती है। सेवा निवृत्ति अथवा सेवा काल में मृत्यु को स्मिति में इन बड़े इच्छितों के बदले सरकार नकद भुगतान करती है, जिसे लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। कई कर्मचारियों के लिए यह राशि सेवानिवृत्ति लाभों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और कई मामलों में यह लाखों रुपये तक पहुंच जाता है।

केंद्रीय कैबिनेट और भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आहट : नितिन नवीन की तैयारी टीम नवीन में युवाओं और महिलाओं को मिल सका है मौका



बिजेपी की नई कार्यकारिणी को घोषणा के बाद अहमदाबाद स्थित पर भी संगठन में फेरबदल की वार्ता है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट में बड़े फेरबदल और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव की अटकलें तेज हुई हैं। सूत्रों के अनुसार, इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ अंजाम दिया जा रहा है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के गठन को अंतिम रूप देने में जुड़े हैं।

कोर्ट ने पुलिस को दी नसीहत कहा- एग्जाम पेपर और प्राइवेट पार्ट में फर्क करें

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को भी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अभिनियम के तहत प्राइवेट ऑफिस के आरोपों के दायरे पर समाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट ने एक कैंडिडेट पर लगे प्राइवेट ऑफिस के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसे गुजरात लोक सेवा आयोग (जीपीएससी) की परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र को तस्वीर खींचकर चार्टरसुपर पर भेजने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी परीक्षा के पेपर को फोटो खींचना और उसे सझा करना आईटी अभिनियम की उस धारा के तहत नहीं आता, जो किसी सरकार के निजी अंगों से जुड़ी निजता के उल्लंघन के लिए बनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराना अनोखा जमीन विवाद सुलझाया

नई दिल्ली। देश के इतिहास के सबसे लंबे चलते आले काठजूनी मामलों में से एक का अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरिद्वार के मासौपुर कला गांव से जुड़े एक अनोखे और 70 साल पुराने जमीन विवाद का निराकरण कर दिया है। यह विवाद अठारह पुराना है कि जिसमें भी इस पर अंतिम फैसला सुनाया, वे दोनों जब तो तब पर भी नहीं हुए थे, जब वे कानूनी दावे-पुर्त शुरू हुआ था। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक परिवार की चार पीढ़ियों द्वारा लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को निराम दे दिया है, जो देश के सभी पूर्व प्रशासकों के कारकाल को विराम देता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद 4 जून 1957 को हरिद्वार के सरसौपुर कला गांव में 15.5 बीघर जमीन को खरीदने से जुड़ा है।

ऑपरेशन सिद्ध के 6 शहीद नेशनल वॉर मेमोरियल में हॉगो अमर

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 सशस्त्र बलों के सैनिकों को नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद कर दिया गया है, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे।

सरकार की छवि खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई, आबकारी अधिकारियों को डी.के. शिवकुमार की चेतानवी

बैंगलूर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार की छवि खराब करने वाली किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार को प्रतिष्ठ बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है। यदि किसी अधिकारी को कार्यक्षेत्र में सरकारी छवि धूमिल होनी है या भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार, लाइसेंस प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों को भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबकारी विभाग से जुड़े सभी कार्य नियमित रूप से होना चाहिए और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जनाता की विश्वासार्थता का समर्थक समझना अधिकारियों के निर्देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार गुप्तसूत्र और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी विभागों से इसी धारणा के अनुरूप काम करने की अपेक्षा करती है। सरकार की सख्त बचत करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नए ऊंचाई देने और उन्हें परंपरा पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। मंत्री सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग के नए उच्चायुक्त दिनेश शिवरेड्डी को भारत-बांग्लादेश मंत्री के बराबर का दर्जा दिया है, जो इस पर नियुक्त किसी भी राजनेता के लिए एक अत्युत्कृष्ट कदम है। अपने पद पर आने के तुरंत बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शिवरेड्डी ने बांग्लादेश न्यायिक प्रणाली के लिए दो साल से बंद पड़ी वीजा संधि को शुरू करने की भी घोषणा की है।

ऑपरेशन सिद्ध के 6 शहीद नेशनल वॉर मेमोरियल में हॉगो अमर

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 सशस्त्र बलों के सैनिकों को नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद कर दिया गया है, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे।

'पीछड़ा' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समूहों की प्रभावी काट के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तर्ज पर, राष्ट्रीय संगठन में भी युवाओं, महिलाओं और विविध महत्वपूर्ण जाति समूहों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की संभावना है। पार्टी का लक्ष्य इन प्रमुख सामाजिक वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करना है। नवीन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं, जब बीजेपी अध्यक्ष नवीन ने कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ लाइवडूब बैठकों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में बदलाव की प्रक्रिया को आखिरी समय तक गोपनीय रखने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर आधिकारिक सूची सख्त रहेगी है। हालांकि, कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारियां सौंपने और

सरकार की छवि खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई, आबकारी अधिकारियों को चेतानवी

बैंगलूर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार की छवि खराब करने वाली किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार को प्रतिष्ठ बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है। यदि किसी अधिकारी को कार्यक्षेत्र में सरकारी छवि धूमिल होनी है या भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार, लाइसेंस प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों को भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबकारी विभाग से जुड़े सभी कार्य नियमित रूप से होना चाहिए और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जनाता की विश्वासार्थता का समर्थक समझना अधिकारियों के निर्देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार गुप्तसूत्र और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी विभागों से इसी धारणा के अनुरूप काम करने की अपेक्षा करती है। सरकार की सख्त बचत करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नए ऊंचाई देने और उन्हें परंपरा पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। मंत्री सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग के नए उच्चायुक्त दिनेश शिवरेड्डी को भारत-बांग्लादेश मंत्री के बराबर का दर्जा दिया है, जो इस पर नियुक्त किसी भी राजनेता के लिए एक अत्युत्कृष्ट कदम है। अपने पद पर आने के तुरंत बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शिवरेड्डी ने बांग्लादेश न्यायिक प्रणाली के लिए दो साल से बंद पड़ी वीजा संधि को शुरू करने की भी घोषणा की है।

ऑपरेशन सिद्ध के 6 शहीद नेशनल वॉर मेमोरियल में हॉगो अमर

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 सशस्त्र बलों के सैनिकों को नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद कर दिया गया है, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे। यह स्थान देशभक्तियों को उनकी अद्वितीय शहादत की गथा से परिचित कराएगा और उन्हें इन वीरों के अदम्य साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देगा। इन छह शहीदों में शामिल हैं: अमर सिंह, जहां उनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए उकेरे जाएंगे।

सड़क दुर्घटना : किसी भी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का नहीं किया पालन सरकारों की लापरवाही से हर साल होती है 1.77 लाख मौतें नई दिल्ली। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.77 लाख लोगों की मौत होती है, जो एक चौकाने वाली कहानी बघा करता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हादसों में भाग्यलों को जान बचाने के लिए पूरी ट्रीमा केयर व्यवस्था को मांग सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन अब तक किसी राज्य में यह पूरी तरह तैयार नहीं है। पिछले 9 महीनों में रान्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट को जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनसे यह स्थिति स्पष्ट साबित हुई है। यद्यपि जा रहा है कि राज्य सरकारों की लापरवाही से हर साल सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।

श्रीप अदालत ने सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए रान्यों को नौ महत्वपूर्ण बदलाव देने के लिए कहा था। इनमें से पांच सबसे जरूरी उपाय हैं- एक समान आपातकालीन फोन नंबर, जीपीएस से लैस एंबुलेंस, गुड स्मॉलिंग कानून, ट्रीमा रिजर्वी और बचाव कार्य के लिए तय प्रोटोकॉल। ये पांच उपाय दुर्घटना के बाद के 'गोल्डन अवॉर' यानी पहले 60 मिनट के दौरान लोगों की जान बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अदालत ने प्रस्तुत किए गए करीब 1200 फॉर द दस्तावेजों में पता चलता है कि देश में सड़क हादसों में होने वाली हर मौत में से दो मीते जिवा आठ रान्यों में होती हैं। यह रान्य हैं- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और ओडिशा प्रदेश शामिल हैं। उनमें से 7 रान्यों ने अभी तक अपने सभी इमरजेंसी नंबरों को एंबुलेंस पर 112 से नहीं जोड़ा है। वहीं, कर्नाटक ने इस संबंध में कोई जांचकारी उपाय नहीं कराया है।

आपातकालीन राहतवा सुविधाओं के निर्माण में दिलाई

श्रीप अदालत के आदेश के 10 साल बाद भी राज्य सरकारें पर जान में से दो मीते जिवा आठ रान्यों में होती हैं। यह रान्य हैं- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और ओडिशा प्रदेश शामिल हैं। उनमें से 7 रान्यों ने अभी तक अपने सभी इमरजेंसी नंबरों को एंबुलेंस पर 112 से नहीं जोड़ा है। वहीं, कर्नाटक ने इस संबंध में कोई जांचकारी उपाय नहीं कराया है।

पंजाब से तमिलनाडु तक कांग्रेस ने बड़े बदलाव की तैयारी, राहुल गांधी संगठन को दौरे नई दिशा

नई दिल्ली। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए देशभर में बड़े संरचनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विभिन्न रान्यों में प्रदेश अध्यक्ष, प्रचारकों और संसद सदस्यों के रूप में व्यापक फेरबदल की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

90 करोड़ के शमशान घाट का मुफ्त संचालन ईशा फाउंडेशन को

नई दिल्ली। बिहार सरकार ने पटना के बांसवाड़ा शमशान घाट को 89.40 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। अब यह विशाल शमशान घाट संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को नि:शुल्क सौंप दिया है। ईशा फाउंडेशन को नि:शुल्क सौंप दिया है। यह शमशान घाट पर लाने वाले 300 रुपये की राशि से लंबी अपेक्षा है, जो एक बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है।

कविता 4.5 एकड़ में फैले विशाल शमशान घाट को पटना

न्यूज गैलरी

बैहर एवं बिरसा में नदी-नालों के उफान वाले क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित एसडीएम ने 1 अगस्त तक जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, उद्बोधन पर होगी कानूनी कार्रवाई

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। वर्षा ऋतु के दौरान आमजन को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैहर उद्वेग विभाग के अनुविभागीय इंस्पेक्टर श्री अर्जुन गुप्ता ने भारतीय नौगिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 26 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 01 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इससे बैहर एवं बिरसा तहसील क्षेत्र को नदियाँ, नालों, बंजर, झरनों तथा तालाबों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने का आशंका है। ऐसी परिस्थितियों में जनताओं की संभालना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं।

आदेश के तहत बैहर एवं बिरसा तहसील क्षेत्र में नदी, नाला, झरना, बंजर और तालाब सहित सभी जलस्रोतों के उद्वेग वाले स्थानों पर आम लोगों के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बाढ़ की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थलों से 100 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश करने को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, जिन प्रखंड क्षेत्रों में भूखंडन अथवा जमीन धरने की आशंका है, वहां भी 100 मीटर के दायरे में आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नदी-नालों एवं अन्य जलस्रोतों में तैराकी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

एसडीएम श्री अर्जुन गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आमजन की सुरक्षा के हित में भारतीय नौगिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एएसपीआर कूट से जारी किया गया है। आदेश से प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति द्वारा 163(5) के तहत सख्त न्यायवाचक में अद्वैत प्रस्ताव कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में फिंगरनुमर वृद्ध प्रदान की जा सकती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत निशेधमत्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नौगिक से अपीली की है कि वे वर्षा के दौरान नदी-नालों और अन्य जलस्रोत वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

ढाई साल बाद भी अधूरा जागपुर घाट पुल इस बारिश भी ग्रामीणों को नहीं मिलेगी राहत

करीब 19.37 करोड़ की लागत से बन रहा उच्चस्तरीय पुल समय सीमा में पूरा होना असंभव

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज़। बालाघाट।

बैरागां नदी पर जागपुर घाट में बन रहा बहुप्रतीक्षित उच्चस्तरीय पुल एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग ढाई वर्ष पहले बड़े उसाह के साथ शुरू किया गया यह निर्माण कार्य अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। पुल निर्माण की निर्धारित समय-सीमा 28 जून 2026 समाप्त होने वाली है, लेकिन मौके की स्थिति यह साफ संकेत दे रही है कि इस अवधि में निर्माण पूरा होना संभव नहीं है। ऐसे में इस वर्ष भी बारिश के दौरान जागपुर सहित आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीणों को बालाघाट आने-जाने के लिए लंबा चकर लगाना पड़ेगा।

करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित हो रहा लगभग 400 मीटर लंबा उच्चस्तरीय पुल क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए ऐसे उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। पुल का निर्माण कार्य 29 जून 2023 को शुरू किया गया था और अनुबंध के अनुसार इसे 28 जून 2026 तक पूरा किया जाना था। लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने में अब केवल कुछ दिन शेष हैं, जबकि पुल का अधिकांश कार्य अभी भी अधूरा है। निर्माण स्थल पर काम की गति निर्धारित समय से धीमी है। सबसे अधिक परेशानी उन ग्रामीणों को होगी जो हर वर्ष बारिश के मौसम में बैरागां नदी के कारण आवागमन को समस्या झेलते हैं। पुल बनने के बाद जागपुर से बालाघाट की दूरी महज दो किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों को पैदल और रातों-रात होकर लगभग 10 से 12 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। बरसत में यहाँ लंबा रास्ता उनको मजबूरी बन जाता है। इस पुल के बनने से जागपुर, छिंदीटोला, रेंगाटोला, एंकाटोला, ओसाटोला, उमराटोला, भांडी, पिपारिया, दोनी, हुड़कोटोला, एकोडी, कासपुर, मदनपुर, अमाटोला सहित दो दर्जन से अधिक गांवों के लगभग 15 से 20 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन



गांवों के लोगों को नदी पार करने या लंबा चकर लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। विशेष रूप से बरसात के दिनों में मरोठों, विद्यार्थियों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। पुल के कई हिस्से तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी कैच का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद पुल पर 38 गैर स्थायी किए जाने हैं। मौजूदा गति को देखते हुए निर्धारित समय में पुल पूरा होना संभव नहीं है। मौके पर काम की रफ्तार बेहतर धीमी दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण का ठेका मेसर्स अम्बिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया है। निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी के कारण कुछ समय पहले विभाग में ठेकेदार का अनुबंध समाप्त (टर्मिनेट) कर दिया था। हालांकि बाद में ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूरा करने का प्रस्ताव दिए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध फिर से बहाल कर दिया। उम्मीद थी कि इनके बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी, लेकिन स्थिति

पहले जैसी ही बनी हुई है। काम की गति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दिया।

जून माह के अंत तक गडर लॉन्चिंग के निर्देश दिए थे - अर्जुन सनोडिया

संतु संभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ठेकेदार का अनुबंध दोबारा समाप्त करना भी आसान नहीं है। संतु संभाग के एसडीओ अर्जुन सनोडिया ने बताया कि यदि इस समय अनुबंध समाप्त किया जाता है तो नई निविदा प्रक्रिया में ही लगभग तीन माहों का समय लग जाएगा। इससे निर्माण कार्य पूरी तरह ठग हो जाएगा और परियोजना में और अधिक विलंब होगा। यही कारण है कि विभाग धीमी गति के बावजूद वर्तमान ठेकेदार से ही कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 4 जून को हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर मृणाल मोघा ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को

जून माह के अंत तक पुल पर गडर लॉन्चिंग का कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और निर्वाह निगरानी रखने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन निर्माण स्थल की मौजूदा स्थिति यह बताती है कि इन निर्देशों का अपेक्षित अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। मौके पर कार्य की गति अभी भी बेहतर धीमी बनी हुई है। जागपुर घाट पुल निर्माण में लगातार हो रही देरी को लेकर पहले ही कई बार जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने प्रशासन तथा निर्माण एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए और समय पर पुल निर्माण की मांग उठाई गई, लेकिन इसके बावजूद परियोजना तय समय पर पूरी नहीं हो सकी।

भीमोड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से तीन युवकों की मौत, छह गंभीर घायल

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। जिले के बैहर खाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहका के भीमोड़ी में शुकवार दोपहर तेज आंधी-तूफान और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले बैहर अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ को गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।



बारिश से बचने वन विभाग के टावर पर चढ़े थे युवक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भीमोड़ी, बिरवा, कोहका और अतरिया के करीब 14 युवक दोपहर में भीमोड़ी तालाब में मछली पकड़ने और नहाने गए थे। इसी दौरान करीब 2 बजे अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी युवक जंगल में लगे वन विभाग के वांच टावर पर चढ़ गए। इसी दौरान टावर से लगे एक विशाल सरई के पैड पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसको चपेट में सभी युवक आ गए।

मृतकों व घायलों में इनका शामिल

हादसे में सलोश बलक (19) पिता दयाल बलक निवासी बिरवा और लक्ष्मी मेरावी (18) पिता श्रीराम मेरावी निवासी बिरवा को मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल इमामसिंह ताराम (32) निवासी भीमोड़ी ने बैहर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं देविमिह सहित छह अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ अन्य को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बैहर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले को जांच शुरू कर दी है। घटना ने पूरे क्षेत्र को शकहोर कर रखा दिया है।

भारत वर्ष में नं. 1. मध्यप्रदेश में भी नं. 1

भारत वर्ष की पहली 9 इंच में डीवीटी में उपलब्ध (भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त) रॉइडान व वाकविहाइड दोनो LC09W

बगैर अनुदान के 2.40/- अनुदान होने पर 1.50/- Kaira RTP 4 Row

साईं ट्रेकर्स/के.के. इंटरप्राइजेस 8770334649

मोती ताराच रोड, नर्मदा नगर बालाघाट 8120467192

आवश्यकता है फिल्ड कार्य हेतु लड़कों की आवश्यकता है

संपर्क करें-पद्मेश सिटी केवल काली पुतली चौक, बालाघाट

सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक

बी.टेक. पॉलिटेक्निक

- कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
- मार्किंग इंजीनियरिंग
- सिविल इंजीनियरिंग
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

ADMISSION + OPEN

सतपुड़ा कॉलेज, तालबारां रोड, गरी-बालाघाट
8262604111, 9425836824 www.satpujraengineeringcollege.com